दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–10)

निर्धारित समय: तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	DTVF/22 (J-A)–M–**GSM (M-I)-2210**	अधिकतम अंक: 250 *Maximum Marks: 250*

Name: Ishwar lal Gurjar **Mobile Number:** ____________________

Medium (English/Hindi): ____________ **Reg. Number:** ____________________

Center & Date: ____________________ **UPSC Roll No.** ***(If allotted)*****:** ____________________

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1. विधियाँ परिवर्तन की शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन जल्दबाजी में निर्मित विधियाँ मंशा अनुरूप कार्य नहीं करतीं और नेक मंशा से बनी विधियाँ अप्रभावी रही हैं। इस संबंध में संसद की प्रभावहीनता के कारण विधि निर्माण में व्याप्त कमियों की चर्चा कीजिये एवं सुदृढ़ विधि निर्माण प्रक्रिया के लिये उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10

Laws can be powerful instruments of change. But badly made ones do not work as intended and well-intentioned ones are ineffective. In this regard, discuss lacunae gripping the law-making due to ineffectiveness of Parliament and suggest measures for robust law-making process. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल के वर्षों में संसद की विधि निर्माण प्रभावहीनता के कई उदाहरण देखने को मिले है। उदा० - तीन कृषि कानूनों की वापस।

- CAA-2020 का विवाद

विधि निर्माण: व्याप्त कमियाँ

↳ (i) 2021 ई. में 13 विधेयकों में से एक भी विधेयक को संसदीय समितियों के पास नहीं भेजा गया। जो चर्चा व बहस की कमी का उदाहरण है।

(ii) 76% बजट को वर्ष 2021 में बिना चर्चा के ही पास किया गया।

Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iii) सांसदों द्वारा रुचि न लेना, — संसदीय समितियों में उपस्थिति दर -50% से भी कम रही।

(iv) संसद की कम होती उत्पादकता

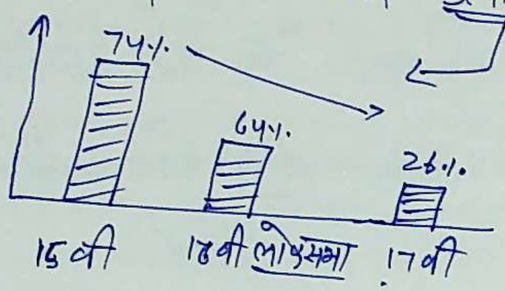

(v) विशेषज्ञता का अभाव (vi) अत्यधिक कार्यबोझ (मंत्री - दोहरी जिम्मेदारी)

उपाय → (A) वन नेशन वन लेजिस्लेशन पोर्टल द्वारा अध्ययन व रिसर्च सामग्री देना

(A) संसदीय समितियों के पास बिल भेजना अनिवार्य

(B) ई-संसद का प्रयोग (डिजिटलीकरण)

(C) UK की तर्ज पर 'संसदीय बजटीय कार्यालय'

(D) चर्चा की संस्कृति बढ़ाना।

अतः नागरिक समाज में विधि के ड्राफ्ट को रखकर व्यापक सहमति से कानून निर्माण हो।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में कॉलेजियम प्रणाली का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

The process for the appointment of judges lies at the heart of an independent judiciary. In this regard critically analyze the collegium system. (150 words) 10

अनुच्छेद -124 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (CJI व मंत्रीपरिषद के परामर्श से करने का प्रावधान है, लेकिन तृतीय जजवाद (1997) में कॉलेजियम प्रणाली (4 जजों की सलाह) की व्यवस्था सामने आई।

स्वतंत्र न्यायपालिका : न्यायाधीशों की नियुक्ति

→(A) शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वतंत्र व दुर्भावना रहित हो।

(B) स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, अतः प्रक्रिया भी स्वतंत्र है

(C) कार्यपालिका के दबाव से मुक्त हो।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

कॉलेजियम प्रणाली की कमियाँ — (*) पारदर्शिता का अभाव

(1) भाई-भतीजेवाद का आरोप

(3) न्यायपालिका द्वारा ही स्वयं की नियुक्ति प्राकृतिक न्याय उल्लंघन

(2) पुरुष-प्रधान प्रणाली (महिलाएँ -12%)

(*) चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था के खिलाफ है

(4) योग्यता की अनदेखी

(*) अनावश्यक विवाद जैसे जस्टिस कर्णन वाद

कॉलेजियम प्रणाली : पक्ष में तर्क

→ (A) स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए जरूरी है
(B) कार्यपालिका से स्वतंत्र है।
(D) सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजों को शामिल व्यापक दायरा है।

आगे की राह → CJI के ऑफिस को RTI के दायरे में लाना, विशेषज्ञता को महत्व देना, सलेक्शन के कारण बताना व पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

3. एक सुदृढ़ और स्वतंत्र रूप से संचालित नागरिक समाज की उपस्थिति सफल और स्थिर लोकतंत्र की पहचान है। इस संबंध में नए भारत के निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

The presence of a strong and freely operating civil society is the hallmark of successful and stable democracies. In this regard critically examine the role of Civil society in making of new India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नागरिक समाज जागरूक व सक्रिय नागरिक संगठनों, स्वैच्छिक समूहों, NGO व नागरिक दबाव समूहों का संयुक्त रूप है, जो सरकार व प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, तथा सेवा की माँग करता है।

जैसे- NGO द्वारा — सेवा वितरण
— फीडबैक (प्रथम)

सुदृढ़ व स्वतंत्र नागरिक समाज : आवश्यकता

→ (क) जनसहभागी लोकतंत्र बनाने में
(ख) शासन को सहयोग व समर्थन
(ग) नीति निर्माण में फीडबैक देने में
उदा० लोकपाल विधेयक के लिए।
(घ) सेवा वितरण में सहायता हेतु।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

भूमिका (A) -> नागरिक

समाज शासन को => लोक नीति

निर्माण — क्रियान्वयन — मूल्यांकन

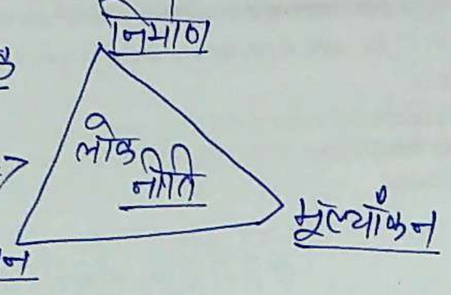

(B) नागरिक अधिकारों की माँग व सुरक्षा
उदा० RTI एक्ट का आन्दोलन
अरूणाचित रॉय द्वारा।

(C) मानवाधिकारों, पर्यावरणीय मुद्दों पर नई चर्चा हेतु जैसे- नर्मदा बचाओ आंदो.
- बीज बचाओ आंदो.

(D) सरकार को फीडबैक व सहायता देना
↳ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा शिक्षा

चुनौतियाँ * नीतिगत लकवा * अनावश्यक विरोध
* विकास कार्य बाधित * विदेशी सहायता का मुद्दा

हालाँकि नागरिक समाज एक जीवंत लोकतंत्र की निशानी है अतः इसे बढ़ावा देना चाहिए

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी कुशलता से G20 में मौजूद अंतर को समाप्त करने के लिये रास्ते एवं साधन खोज सकता है और इसे साझा हित के मंच में रूपांतरित कर सकता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The success of India's G20 Presidency will depend on how deftly India can find paths and instruments to bridge the divides plaguing the G20 and turn it into a platform of shared interest. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

G-20 की आगामी बैठक की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है जिसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती विभाजित समूह G20 को साझा हित मंच में बदलना है।

जैसे- चीन - अमेरिका (प्रतिस्पर्धा)
रूस - अमेरिका विवाद

G-20 के समक्ष चुनौतियाँ : भारत की भूमिका

↳ (i) रूस- यूक्रेन संघर्ष पर स्पष्ट दृष्टिकोण का निर्माण करना व जल्दी ही युद्धविराम समझौता => भारत के रूस से मैत्रीपूर्ण सम्बंध, भारत मध्यस्था करे

(ii) जलवायु परिवर्तन उत्सर्जन प्लान में व्यापक अंतर व विकसित राष्ट्रों द्वारा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

जिम्मेदारी से भागना => भारत अन्तर्राष्ट्रीय सौलर एलायंस (ISA) द्वारा एक मंच व 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड' का निर्माण

(iii) चीन-अमेरिका की बढ़ती प्रतिस्पर्धा व चीन का उग्रवादी रुख - भारत अमेरिका की हिन्द पैसेफिक नीति व क्वाड में चीन को संतुलित कर सकता है।

(iv) ग्लोबल कॉमन टैक्स व बेस इरोजन प्रॉफिट स्फीटिंग संधि को मूर्त रूप देना

(v) जलवायु वित्त, कार्बन क्रेडिट व कार्बन न्यूट्रल टारगेट तथा SDG-2030 में भारत द्वारा समन्वय

अतः भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में 'वन वर्ल्ड' की अवधारणा व समावेशी प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. डेटा संरक्षण कानून में राज्य की निगरानी शक्ति के साथ-साथ व्यक्तिगत गोपनीयता को स्पष्ट करना चाहिये। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Data protection law should spell out individual privacy along with state surveillance power. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

'डेटा संरक्षण कानून' द्वारा डाटा के स्थिरीकरण, संरक्षण, भंडारण व प्रसंस्करण पर व्यापक नियामकीय ढांचा बनाने का प्रयास किया गया है।

डेटा संरक्षण कानून: व्यक्तिगत गोपनीयता का मुद्दा

(i) 'डेटा' तकनीकी वर्ल्ड का न्यू ऑयल है, भारत में 65 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर है अतः व्यापक डेटा उत्पन्न होता है। कानून में डेटा को दो भागों में बांटा

(A) व्यक्तिगत डाटा
- व्यक्ति की पहचान
- नाम, मोबाइल नम्बर
- पता व अन्य

(B) गैर-व्यक्तिगत डाटा
- आयु, लिंग व पसंद के पैटर्न का डाटा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(ii) व्यक्तिगत डेटा को साझा नहीं करना व व्यक्ति का अपने डेटा पर अधिकार होना। निजता की स्वतंत्रता के लिए डिजिटल अधिकार प्रदान करना।

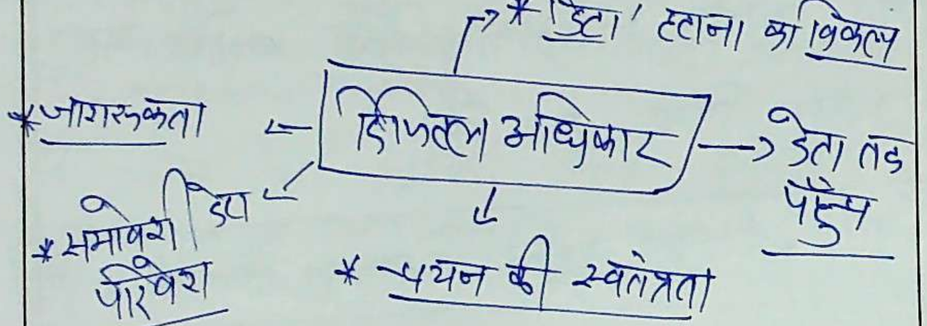

डिजिटल अधिकार
- * डेटा हटाना का विकल्प
- डेटा तक पहुँच
- * चयन की स्वतंत्रता
- *समावेशी डेटा परिवेश
- *जागरूकता

(iii) गैर-व्यक्तिगत डाटा का उपयोग नीति-निर्माण में किया जाना चाहिए। जैसे- पसंद, चयन व अन्य डेटा।

आगे की राह - डेटा संरक्षण कानून को व्यापक बनाते हुए, Right to forget व डिजिटल अधिकार दे कर नागरिकों की गोपनीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. दल-बदल विरोधी कानून गैर-सैद्धांतिक दल-बदल द्वारा लोकतंत्र के क्षरण के विरुद्ध सुरक्षा के लिये लाया गया था, हालाँकि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Anti-defection law was brought to protect against the subversion of democracy by unprincipled defection, however, it has failed to achieve its objective. Critically Examine. (150 words) 10

52 वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ई. में "आया राम, गया राम" की प्रवृत्ति के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून लाया गया था।

उद्देश्य
- * धनबल को राजनीतिक प्रयोग से रोकना जैसे- विधायकों की खरीद
- * जनमत की रक्षा हेतु
- * लोकतांत्रिक सरकार की स्थिरता व सुरक्षा हेतु
- * राजनीतिक भ्रष्टाचार कम करने हेतु
- * हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना
- * गठबंधन की रक्षा
- * अवसरवादी राजनीति पर रोक हेतु

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

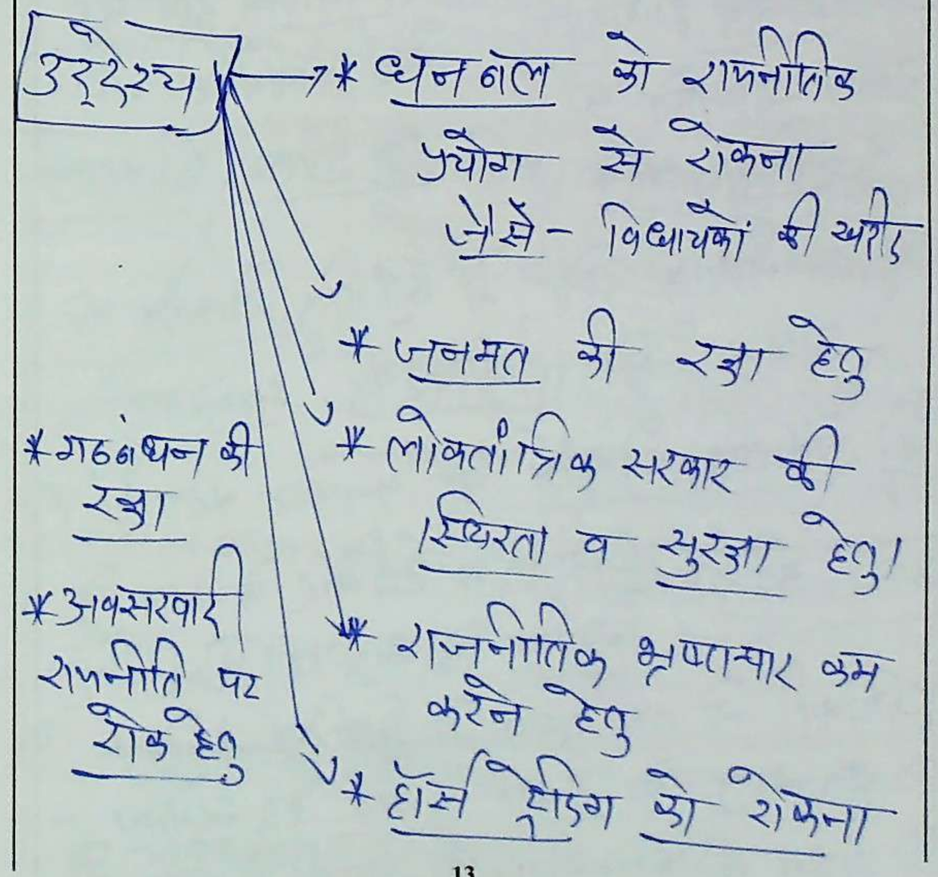

Copyright – Drishti The Vision Foundation

लेकिन वर्तमान में 43% विधायक दल बदल के चुनाव जीते है तथा 2016-20 के मध्य 13 सांसदों ने चुनाव जीतने के लिए दल बदला।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

विफलता के कारण

(i) संख्या को आधार बनाना अतार्किक = (2/3)

(ii) राजनीतिक दल पर कोई जवाबदेही नहीं। - दल विलय की अनुमति

(iii) पीठासीन अधिकारी द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करना

(iv) राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव जैसे- परिवारवाद, अवसरवाद

(v) प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर करता है।

आगे की राह - (1) कलकत्ता हाईकोर्ट के हाल के निर्णय के अनुसार पीठासीन अधिकारी को तय समय में निर्णय देना चाहिए।

(2) दल-बदलू को 6 वर्ष चुनाव हेतु अयोग्य

(3) कानून की पुनः समीक्षा (4) राष्ट्रपति/राज्यपाल को शक्ति देना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक स्तर और दायरा इसे विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक बनाता है। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द) 10

The sheer scale and scope of the Swachh Bharat Abhiyan makes it one of the largest cleanliness drives in the world. In this regard, critically evaluate the success of Swachh Bharat mission. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

2 अक्टूबर 2014 को पूरे भारत को खुले में शौचमुक्त (ODF) बनाने के लिए 5 वर्ष हेतु 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत हुई, जिसे हाल ही में इसके चरण के लिए बढ़ा दिया।

प्रावधान

(1) प्रति परिवार शौचालय निर्माण हेतु - 12 हजार की सहायता

(2) जागरूकता के लिए वर्ष में स्वच्छता हेतु श्रम दान की

(3) स्वच्छ भारत ब्रांड एम्बेसडर द्वारा सामाजिक प्रभाव द्वारा जन जागृति

(4) सामुदायिक शौचालयों के लिए पंचायतों को स्वच्छता अनुदान (15वें वित्त आयोग)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(प्रभाव) — * 2019 तक 30 करोड़ से अधिक पक्के शौचालयों का निर्माण हुआ

* स्थानीय स्वशासन निकायों में स्वच्छता प्रतिस्पर्धा के लिए सूचकांक — (शहरी विकास मंत्रालय) - जागरूकता बढ़ी

* ठोस अपशिष्ट निपटान, पेयजल सुविधा, सुलभ शौचालय में अत्यधिक प्रगति हुई (आर्थिक समीक्षा 2020 के नेट नेसेसिटी इन्डेक्स में सुधार)

(सीमाएँ) * NFHS-5 के अनुसार अभी भी गाँवों की 50% से अधिक आबादी खुले में शौच करती है।

* शौचालय निर्माण मात्र दिखावा है उपयोग बेहद कम करते हैं।

हालाँकि स्वच्छ भारत अभियान ने एक आन्दोलन के रूप में जागरूकता पैदा की

Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. भारत-नेपाल ने 75 वर्ष पहले आधिकारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद से बहुआयामी और गहन संबंध साझा किये हैं। लेकिन इस संबंध में कई अंतर्विरोध भी देखने को मिले हैं। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

India-Nepal has shared multidimensional and dense relations since the beginning of official diplomatic relations 75 years ago. Yet the relationship is marked by several contradictions. Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत व नेपाल के मध्य ऐतिहासिक, भाषायी, नृजातीय, धार्मिक व सांस्कृतिक सम्बंध - 'रोटी-बेटी' के स्तर के हैं।

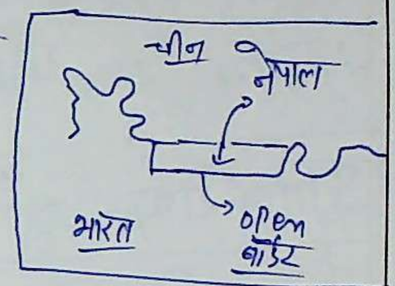

बहुआयामी व गहन सम्बंध : 75 वर्ष

→ (i) भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक, निर्यातक व निवेशक राष्ट्र है।

(ii) नेपाल के कुल आयात का 50% से भी अधिक भारत करता है।

(iii) 1950 की मैत्री संधि से ही दोनों के मध्य खुली सीमा है, नेपालियों को भारत में वीजा फ्री एन्ट्री है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iv) भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियो. बांध निर्माण, रेलवे लिंक, तेल पाइपलाइन जैसे बुनियादी अवसंरचना में निवेश किया

(v) उत्तर-बिहार के नेपाली मधेशी समुदाय से पारिवारिक सम्बन्ध है।

अंतर्विरोध : चुनौतियाँ

(A) सीमा विवाद - (कालापानी व लिपुलेख क्षेत्र)

(B) भारत के प्रति Big brother सिन्ड्रोम

(C) चीन का नेपाली राजनीति, अर्थव्यवस्था में बढ़ता दखल जैसे - CPN पार्टी

(D) 2015 के संविधान ड्राफ्ट पर विरोध के बाद अविश्वास बढ़ा (E) 1950 की संधि की व्याख्या / समीक्षा की मांग।

भारत को गुजराल डॉक्ट्रिन व नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुसार नेपाल से सम्बन्धों को बेहतर करना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

9. चीन अपने वैश्विक विस्तारवाद के एक भाग के रूप में दक्षिण एशिया में भारत के हितों को कमज़ोर कर रहा है। इस संदर्भ में चीन के प्रति-आधिपत्य और वृहत् क्षेत्रीय स्थिरता के लिये एक कदम के रूप में सार्क को पुनः सशक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

China as part of its global expansionism, is chipping away at India's interests in South Asia. In this regard discuss the need to reinvigorate SAARC as a step to counter-hegemonic China and for greater regional stability. (150 words) 10

भारत-चीन के मध्य 3000km लम्बी सीमा है तथा चीन भारत को BRI व 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति के तहत दक्षिण एशिया में भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है।

सार्क को पुनः सशक्त करने की प्रासंगिकता

(i) सार्क का दक्षिण एशियाई पहचान से जुड़ा होना व भारतीय उपमहाद्वीप

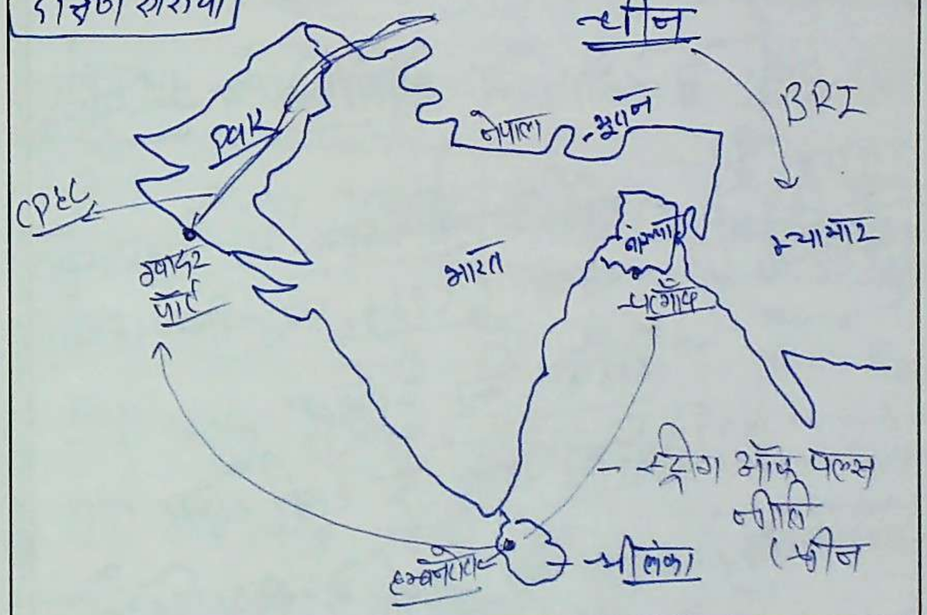

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

के साझे हितों के लिए एक साझा मंच के रूप में आवश्यक है।

(ii) सार्क - दक्षिण एशिया के आठ देशों का एक पुराना संगठन (1985) है अतः भारत को इसका प्रयोग चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी व 'ऋण जाल कुनीति' के खिलाफ करना चाहिए।

(iii) सार्क के देशों में भौगोलिक व सांस्कृतिक जुड़ाव है।

चुनौतियाँ
- सार्क में पाकिस्तान का नकारात्मक रूख (CPEC पर चीन पक्षधारिता)
- बैठकों का अभाव
- द्विपक्षीय विवाद का हावी होना

आगे की राह - भारत को सार्क के साथ बिम्सटेक को भी सक्रिय मंच बनाना चाहिए। नेबरहुड फर्स्ट, सागर विजन, एवं गुजराल डॉक्ट्रीन द्वारा चीन के प्रति भारतीय पक्ष खड़ा करने का प्रयास करना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

10. क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) का समय आ गया है जो कई छोटे राज्यों के सृजन के साथ भारत के संघीय मानचित्र का पुनर्निर्माण कर सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Do you think that the time has come for a second States Reorganization Commission (SRC) that can redraw India's federal map, creating many smaller states? Critically Examine. (150 words) 10

भारत में बढ़ती स्वायत राज्यों व क्षेत्रों की माँग जैसे - बोडोलैण्ड, गोरखालैण्ड, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, ग्रेटर नागालैण्ड की माँग के कारण दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की संभावना को तलाशा जा सकता है।

दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग: प्रासंगिकता

(i) क्षेत्रीय माँगों को सन्तुष्ट करने हेतु।

(ii) बढ़ता क्षेत्रवाद → अलगाववाद को रोकने हेतु

(iii) एक लम्बे समय (1953) के बाद अब 70 वर्षों का समय नई संघीय ढाँचे की समीक्षा समय की माँग है।

(iv) राज्यों के बड़े आकार → प्रशासनिक दिक्कत (जैसे आरपीएस)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iv) राज्यों में सीमा विवाद समाधान हेतु
जैसे - असम - मिजोरम विवाद
- कर्नाटक - महाराष्ट्र विवाद (बेलगाम)

(vi) जल विवाद, भाषायी विवाद व असमान विकास के कारण माँग।

चुनौतियाँ - (A) राज्यों का पुनर्गठन जटिल प्रक्रिया है यह राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को अनावश्यक खतरे में डाल देगी
(B) भाषा, क्षेत्रीयता व क्षेत्रवाद के संघर्ष को बढ़ा सकती है।
(C) अन्य क्षेत्रों से भी मांग बढ़ेगी

आगे की राह - दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने की बजाय शक्तियों के विकेन्द्रीकरण द्वारा स्थानीय सरकारों को सशक्त करना। समावेशी विकास को बढ़ाना, सहकारी संघवाद को मजबूत करना व टीम इंडिया की भावना से काम करने की जरूरत है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. "सहकारी संस्थाएँ देश के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन शायद ही कभी नीति नियोजन के केंद्र बिंदु में होती हैं।" इस कथन के आलोक में सहकारी संस्थाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न समस्याओं और सहकारिता क्षेत्र के प्रबंधन के लिये एक नए केंद्रीय मंत्रालय के निर्माण के औचित्य पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

"Cooperatives play a vital role in the country's development but are seldom the focus of policy planning". In light of this statement discuss the various issues faced by Cooperatives and the rationale for the creation of a new Union Ministry to oversee the cooperatives sector. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सहकारी संस्था साझे हितों के लिए संगठित लोगों का स्वैच्छिक समूह होता है, जो "एक सबके लिए, सब एक के लिए" के आदर्श पर काम करता है।

प्रावधान
- संविधान के अनुच्छेद 19(c) के तहत मूल अधिकार है।
- नीति निर्देशक तत्वों (43B)
- संविधान के भाग-9(B) में
- नया सहकारी मंत्रालय

भूमिका - (i) साझे हितों की रक्षा व लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति के सामूहिक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

प्रयास करना जैसे- अमूल द्वारा दुग्ध उत्पादकों के हित (विपणन, प्रसंस्करण)

* सशक्तिकरण
  - नागरिक सशक्तिकरण
  - आर्थिक सशक्त.
  - महिला सशक्तिकरण जैसे- कुडुम्बश्री
* सहकारी समितियाँ
  - ऋण [पहुँच, उपलब्धता]
  - वित्तीय समावेशन (4)
* सेवा वितरण को प्रभावी बनाने में
* निर्धनता उन्मूलन कम करना, स्वरोजगार बढ़ाना आय वृद्धि करना

समस्याएँ
- → * केन्द्रीय सहकारी नीति नहीं
- → वन साइज फिट फॉर आल दृष्टिकोण
- → डिजिटलीकरण का अभाव
- → राजनीतिक दखलअंदाजी
- भ्रष्टाचार (महाराष्ट्र को. बैंक)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सहकारी मंत्रालय का औचित्य

(i) पहले कृषि मंत्रालय में सहकारी क्षेत्र पर ध्यान नहीं अब स्वतंत्र मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय महत्व

(ii) राष्ट्रीय सहकारी नीति द्वारा प्रोत्साहन

(iii) मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसायटी का बेहतर नियमन होगा।

(iv) प्रशासनिक दक्षता बढ़ोतरी होगी

(v) सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को 4 लाख की सहायता डिजिटलीकरण करने के लिए दी जायेगी।

अतः सहकारिता को पुनः आन्दोलन का रूप देने में सहकारी मंत्रालय सहायक होगा जो SDG 1, 2, 3, 4 की प्राप्ति कर सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

12. "पंचायत की आवाज लोगों की आवाज है" और 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिये सही दिशा में बढ़ाया गया कदम था कि लोगों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जाए। हालाँकि इस अधिनियम के लागू होने के तीन दशक से अधिक समय के बाद भी पंचायत की आवाज में दृढ़ता की कमी है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

"The voice of the Panchayat is the voice of the people" and the 73rd constitutional amendment act was a step in the right direction to ensure that the voices of the people are heard loud and clear. However, even after more than three decades of the enforcement of this act, panchayat's voice lacks strength. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन (ग्रामीण) के रूप में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन वर्तमान में पंचायतों के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं

वित्त - पंचायतों के स्वयं के वित्त स्रोत मात्र 6% है जबकि जर्मनी व ब्राजील में यह 40% तक है

(i) पंचायतें वित्त के लिए 96% राशि हेतु हस्तांतरण (राज्य वित्त आयोग) पर निर्भर

शक्तियों का अभाव - संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय सौंपे

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

गए लेकिन राज्यों ने विषयों व शक्तियों का हस्तांतरण नहीं किया - जैसे राजस्थान में 22 विषय

भ्रष्टाचार -> (i) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार पंचायतों को प्राप्त कुल बजट के 30% की अनियमितता है।

(ii) सरपंच पति / प्रधानपति द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा है।

क्षमता की कमी - पंचायतों को स्वच्छता, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा जैसी सेवाएँ दी गई लेकिन कर्मचारियों, बजट का अभाव है। भवन, कम्प्यूटर व अन्य सामग्री का भी अभाव है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

आगे की राह -① मैसूर घोषणा पत्र के तहत पंचायतों के प्रशासन का क्षमता निर्माण करना।

② सामाजिक अंकेक्षण व पंचायत नागरिक घोषणा पत्र द्वारा जनसहभागिता बढ़ावा देना

③ पंचायतों को SDG लक्ष्यों से जोड़ना जैसे राजस्थान पंचायत SDG सूचकांक।

④ डिजिटलीकरण - पंचायतों को ई-स्वराज पोर्टल, वाइब्रेंट डिजिटल ग्राम सभा डैशबोर्ड, स्वामित्व योजना।

सहभागी लोकतंत्र व पंचायतों का सशक्तिकरण करने के लिए शक्तियों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. वर्षों से चुनावों के आयोजन और परिणामों की उनकी निष्पक्षता के लिये सराहना की गई है, हालाँकि चुनावी प्रणाली में कुछ कमियाँ भी सामने आई हैं। इस संबंध में देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

While conduct and outcome of elections over the years have been appreciated for fairness, some shortcomings have also emerged in the electoral system. In this regard discuss the need for electoral reforms in the country. (250 words) 15

भारत में अनुच्छेद -324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन है, जो आजादी के बाद से ही स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से लोकसभा, विधानसभा के चुनाव करवाता रहा है।

चुनाव प्रणाली : कमियाँ

- 43% लोकसभा सदस्य आपराधिक मामलों में आरोपी
- वोटबैंक, जातिवादी राजनीति का चलन
- धनबल का प्रयोग अधिक
- साम्प्रदायिक राजनीति
- वोट प्रतिशत अभी भी कम है (68%)
- राजनीतिक दलों में चुनावी चन्दे की प्रणाली

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

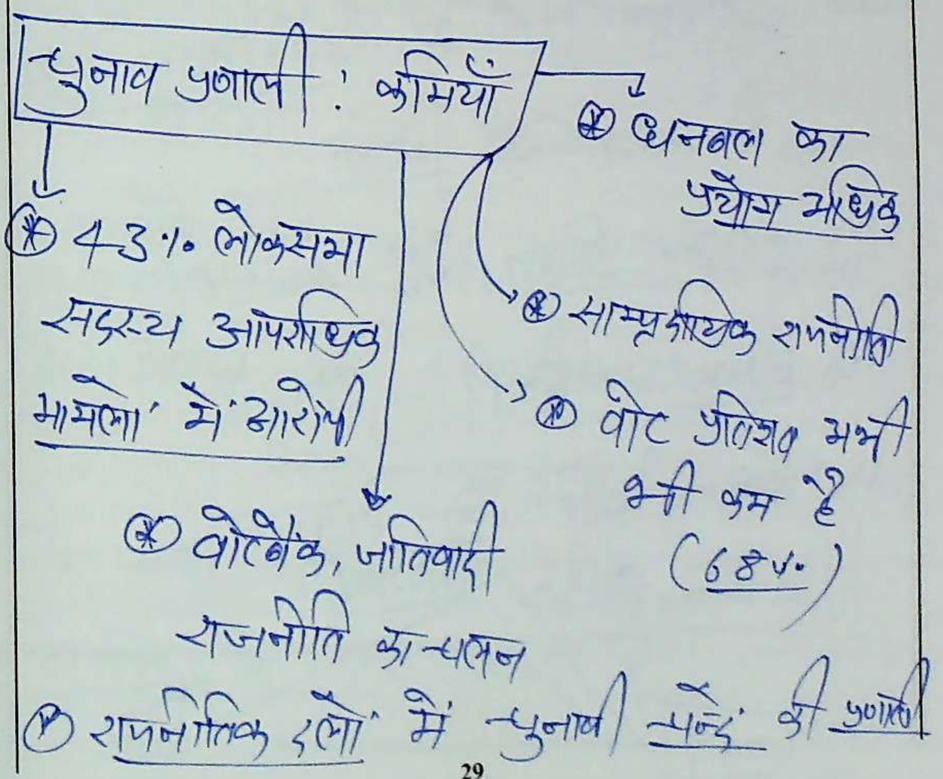

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनाव सुधार : आवश्यकता

(i) स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। सुधार निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ii) राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन जैसे- भड़काऊ भाषण

(iii) डिजिटल दौर में ऑनलाइन वोटिंग की माँग के कारण

(iv) मतदान प्रतिशत को बढ़ाना।

(v) EVM सम्बंधी चुनौतियाँ

(vi) अपराधीकरण को रोकना

(vii) राजनीतिक दलों ->

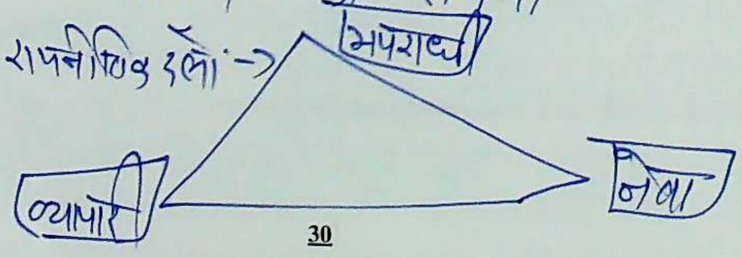

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

उपाय - (i) राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाना।

(ii) आदर्श आचार संहिता को वैधानिक रूप देना

(iii) लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की समीक्षा करना व निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति देना।

(iv) मतदाता सूची के अद्यतन हेतु ब्लॉक चैन तकनीक का उपयोग करना

(v) आधार कार्ड + voter ID link

अतः चुनाव सुधार बदलते समय के साथ चुनावों को अधिक समावेशी बनाने के लिए जरूरी है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का रणनीतिक महत्त्व व्यापक क्षेत्र में विकास को आकार देने की भारत की क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण कारक बना रहेगा। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

The strategic significance of the neighborhood-first policy will remain a key factor in India's ability to shape developments in the wider region. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत ने पड़ोसी देशों से सक्रिय सम्बंध स्थापित करने के लिए 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी को अपनी विदेश नीति का केन्द्र बनाया है यह 'गुजराल सिद्धान्त' का अगला पड़ाव है।

नेबरहुड फर्स्ट : रणनीतिक महत्त्व

(i) भारत अपने 8 पड़ोसी देशों के साथ 15000 km लम्बी भू-सीमा साझा करता है अतः

क्षेत्र (दक्षिण एशिया) ⟶ राष्ट्र की समृद्धि
की समृद्धि से

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(ii) भारत का पाकिस्तान, चीन के साथ ऐतिहासिक सीमा विवाद है अतः शक्ति संतुलन के लिए अन्य राष्ट्रों पर भारत का प्रभाव हो जैसे- नेपाल, भूटान

(iii) भारतीय उपमहाद्वीप की परिकल्पना के अनुसार भारत के अन्य देशों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक (नेपाल, भूटान) व नृजातीय -भाषाई सम्बंध है।

(iv) आर्थिक महत्व की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। निर्यात को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी

(v) सुरक्षा स्रोत - बफर स्टेट की सुरक्षा व सुरक्षा, सामरिक महत्व को बढ़ावा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(प्रभाव) -> पड़ौसियों को वरीयता देना-
जैसे- नेपाल (open बॉर्डर)
भूटान (संरक्षण
* चीन को काउंटर करने हेतु
* आर्थिक महाशक्ति हेतु
* बहुपक्षीय सहयोग जैसे - सार्क, बिम्सटेक, हिन्द महासागर रिम एसोसियशन, आसियान, SCO में समर्थन हेतु।
* वैश्विक मंचों पर सहयोग हेतु- UNSC में सीट पाने, NSG में एन्ट्री।
अतः भारत की नेबर हुड पॉलिसी भारत को दक्षिण एशिया के साथ-साथ वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए जरुरी है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिये और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the constitutional position and explain the process of election of the President of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अनुच्छेद -52 के अनुसार
भारत का एक 'राष्ट्रपति' होगा जो राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख व संसद (विधायिका) का भाग होगा।

संवैधानिक स्थिति

(A) संवैधानिक प्रमुख के रुप में सरकार के सभी आदेश, कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों व समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते है।
(B) वह तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। युद्ध की घोषणा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

व समाप्ति उसके नाम से होगी।

(ड) कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून बनता है।

(ज) वह देश का प्रथम नागरिक होता है

निर्वाचन प्रक्रिया

↳ अनुच्छेद - 55, 56 में निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन - आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। (एकल संक्रमणीय मत)

निर्वाचक मण्डल - लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कमियाँ → अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के कारण अप्रभावी है।

* निर्वाचन आधार सीमित
* नाममात्र की शक्तियाँ

हालाँकि भारत ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया है अतः भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है; बावजूद इसके उनके पास विवेकाधिकार शक्तियाँ भी है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. सीमा पार जल विवाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हमेशा से विवाद का एक विषय रहा है। भारत में सीमा पार नदी प्रबंधन से संबद्ध मुद्दों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Transboundary water disputes have always been a bone of contention between India and its neighboring countries. Discuss the issues associated with Transboundary River management in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत अपने आठ पड़ोसी राष्ट्रों के साथ 15000 km से अधिक भूमि-सीमा साझा करता है, जिसके कारण सीमांकन की अस्पष्टता से कई देशों के साथ नदी जल विवाद उपस्थित है जैसे –

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सीमा पर नदी प्रबंधन : मुद्दे

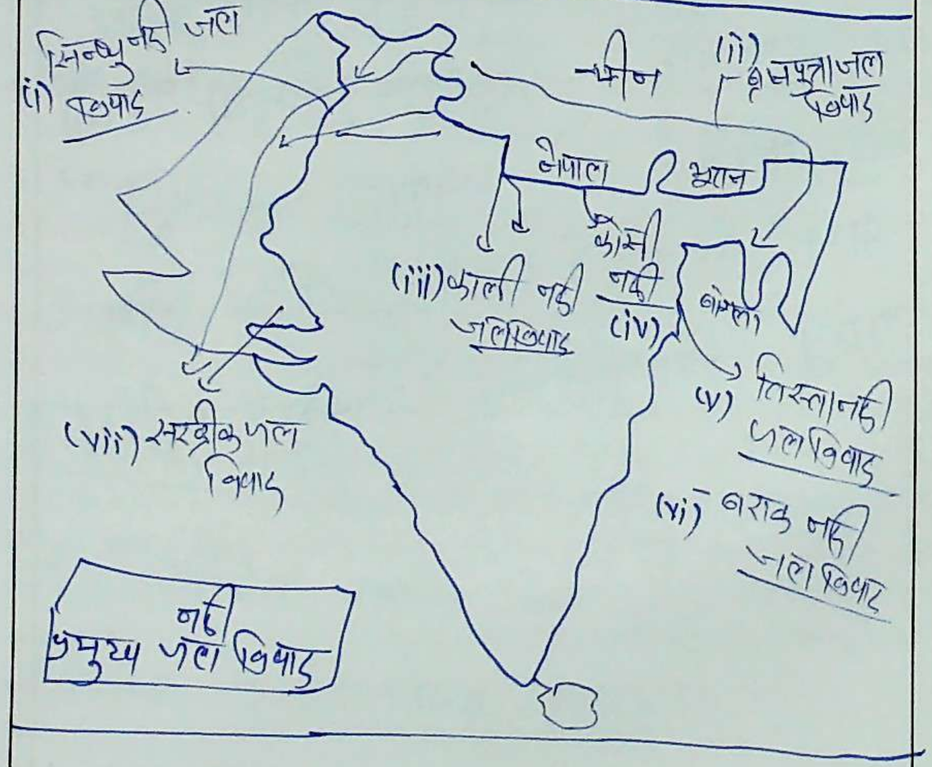

(i) अस्पष्ट सीमांकन – भारत-चीन, भारत-पाक व भारत-नेपाल की सीमा पर सीमा-विवाद है जिससे नदी जल विवाद को बढ़ावा मिला जैसे – भारत-नेपाल कालापानी-लिपुलेख विवाद पूर्वी शारदा के कारण

(ii) नदी प्रबंधन के मानक प्रारूप के अभाव के कारण, राष्ट्रों द्वारा अपने हितों को प्राथमिकता जैसे – चीन द्वारा ब्रह्मपुत्रा नदी पर बांध निर्माण।

(iii) हाइड्रोलिक वॉटर डेटा का अभाव

(iv) आपसी संवाद मंच का अभाव

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रगति – (i) भारत पाक सिन्धु जल विवाद समझौता (1960) को सफलता का मॉडल बनाना चाहिए

(ii) भारत-चीन के मध्य ब्रह्मपुत्र व सतलज के हाइड्रोलिक डेटा साझाकरण समझौता।

(iii) भारत-बांग्लादेश के मध्य गंगा समझौता (फरक्का बांध) का समाधान

आगे की राह – भारत को संवाद द्वारा तिस्ता व बराक नदी पर समझौता कर, सिंधु-आयोग की तर्ज पर सभी देशों के मध्य एक नदी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन करना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. संघर्षी संघवाद उस संविधान के लिये अभिशाप है जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और सहकारिता की इच्छा रखता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Combative federalism is anathema to the Constitution which prescribes cooperation and collaboration between the Centre and the States. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संघर्षी संघवाद से आशय केन्द्र व राज्यों तथा राज्यों व राज्यों के मध्य सहयोग की बजाय आपसी आरोप-प्रत्यारोप करने से है।

जैसे- 9 राज्यों द्वारा CBI की सामान्य सहमती वापस लेना

संघर्षी संघवाद के दुष्परिणाम / अभिशाप

(i) सहकारी संघवाद को कमजोर करता है जैसे- NGT के मामले में विवाद

(ii) केन्द्र-राज्यों में आपसी अविश्वास को बढ़ाता है जैसे- कृषि कानून विवाद

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iii) यह शक्तियों के विभाजन (7वीं-अनुसूची) की मूल भावना के खिलाफ है।

(iv) यह रचनात्मक व प्रतिस्पर्धी संघवाद की संभावना को कम करता है।

(v) जनता के कल्याण की अनदेखी जैसे- पश्चिमी बंगाल द्वारा PM आयुष्मान योजना लागू न करना

आगे की राह- (1) संघर्षी संघवाद से सहकारी संघवाद की ओर बढ़ने के लिए अन्तराज्यीय परिषद (की बैठक) को समय पर करना, जो पिछले

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सात वर्षों में नहीं हुई।

(2) क्षेत्रीय परिषदों को रचनात्मक, सक्रिय बनाना।

(3) नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना जैसे- SDG सूचकांक

(4) टीम इंडिया की भावना से काम

(5) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

(6) राज्यों के हितों व केन्द्रीय हितों में सन्तुलन बनाना।

अतः संघर्षी संघवाद संविधान के मूल भाव के खिलाफ है इसकी जगह प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. देश में कारागार प्रशासन के समक्ष विद्यमान संकटकारी मुद्दों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

There is a need to reflect upon the issues plaguing the prison administration in the country. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

NCRB के अनुसार भारत में 70% से अधिक विचाराधीन कैदी है, तथा कारागार क्षमता से 3 गुणा अधिक कैदी है।

कारागार प्रशासन : संकटकारी मुद्दे

(i) जेल अवसंरचना की खस्ता हाल हालत, पेयजल, स्वच्छता व मानवीय जीवन आवास सुविधा का अभाव है।

(ii) जेलों में गुटबंदी, समूहवाद, हिंसक संघर्ष व आपराधिक माहौल है

(iii) मानवाधिकार आयोग के अनुसार भारतीय जेलों में कैदियों के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

रहने की दशा मानवोचित नहीं है।

(iv) कारागार में भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधि।

(v) बेगार व निम्न भोजन व्यवस्था

(vi) कारागार प्रशासन में मानव संसाधन की कमी, जेल प्रहरी व जेलर के एक चौथाई पद खाली है।

आगे की राह - (i) कारागार प्रशासन के क्षमता निर्माण हेतु एक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने की जरूरत है।

(ii) कारागार आचरण नियमावली को अद्यतन करना होगा

(iii) बजटीय व संसाधन प्रावधानों को स्पष्ट करना होगा।

(iv) कैदियों को योग, साक्षरता व

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

व्यायाम गतिविधियों तथा सुधार रचनात्मक कार्यों को संलग्न करना।

(v) रिक्तियों की भर्ती करना

अतः कारागार प्रशासन को तकनीकी समर्थन (डिजिटलीकरण) द्वारा कुशल व प्रभावी बनाया जा सकता है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं को अपनाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संगठनात्मक ढाँचे की व्याख्या कीजिये और चर्चा करिये कि SCO की सदस्यता भारत के लिये कैसे प्रासंगिक है? (250 शब्द) 15

Explain the organizational structure of Shanghai Cooperation Organization (SCO) and discuss how SCO's membership is relevant to India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

'SCO' की स्थापना चीन के नेतृत्व में मध्य एशियाई देशों व रूस के साथ मिलकर क्षेत्रीय सहयोग, समृद्धि के लिए एक मंच के रूप में की है। भारत व पाकिस्तान को 2017 ई. में इसका सदस्य बनाया गया। हाल ही में ईरान को सदस्यता दी गई।

संगठनात्मक ढाँचा
- मुख्यालय – बीजिंग/शंघाई
- सदस्य संख्या – 8 (ईरान)
- RATS
- सहयोग क्षेत्र – ऊर्जा, तकनीक, आतंकवाद, शांति संवाद व भू-राजनीतिक विवाद

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत: प्रासंगिकता

(1) भारत की मध्य एशिया जुड़ो नीति के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकता है।

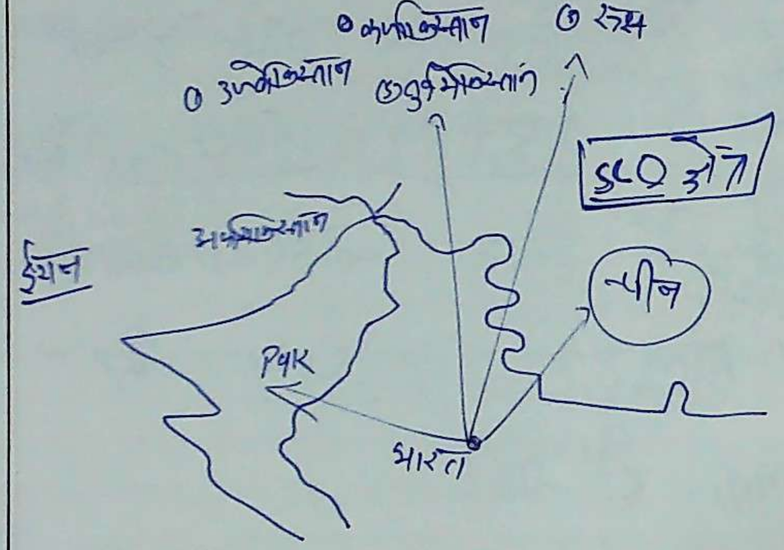

(2) अफगानिस्तान में शांति व स्थिरता के लिए प्रयास हेतु एक मंच।

(3) मध्य एशिया से तापी (TAPI) परियोजना। (तेल गैस पाइपलाइन)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) भारत के रूस, कजाकिस्तान से द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबूत

रूस – रक्षा उपकरण

कजाकिस्तान – यूरेनियम

(5) SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी विंग द्वारा लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद पर नियंत्रण व कार्यवाही कर सकेगा।

(6) मध्य एशिया व अफगानिस्तान में चीन व पाकिस्तान की उपस्थिति को काउंटर करना

चुनौतियाँ – चीन – रूस – पाकिस्तान गुट की बढ़ती नजदीकियाँ

अतः भारत को सावधानी के साथ SCO कराना है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. न्यायपालिका पर वादों/मामलों के भार को कम करने के लिये ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है, लेकिन इसने न्याय प्रणाली में कई चुनौतियों को जन्म दिया है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Tribunals are established to reduce the case load of the judiciary but it has given rise to multiple challenges in justice system. Critically discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

न्यायपालिका में 4.7 करोड़ केस लंबित है, जिनमे 80 हजार केस 30 वर्षों से भी पुराने है, जो न्याय प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करता है।

ट्रिब्यूनल्स का महत्व : उपयोगिता

(i) पर्यावरणीय जैसे विशेषज्ञतापूर्ण मुद्दों पर NGT के गठन से पर्यावरणीय विवादों के निपटान में तेजी आयी।

(ii) राजस्व विवाद व प्रशासनिक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

विवादों के समाधान में भी तेजी व सक्रियता आई है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(iii) ट्रिब्यूनल्स द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में व्यावहारिक पक्ष व विशेषज्ञता का समावेश हुआ
जैसे नदी जल विवाद प्राधिकरण

चुनौतियाँ - (A) ट्रिब्यूनल्स की धीमी कार्यप्रणाली के कारण लम्बित मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई

(B) ट्रिब्यूनल्स के क्षेत्राधिकार का निर्णय भी विवादास्पद है

(C) सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों की बाढ़ आना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(ग) अनावश्यक वित्तीय बोझ
(घ) जटिल प्रणाली

आगे की राह - (i) एक अपीलीय न्याया० की स्थापना, जो सर्वोच्च न्यायालय के बोझ को कम करे
(ii) डिजिटलीकरण - जैसे- जस्टिस क्लॉक, ई-कोर्ट
(iii) ट्रिब्यूनल्स की संख्या कम कर एक क्षेत्र के लिए एक ही न्यायाधिकरण जैसे- अखिल भारतीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण।

अतः न्याय प्रणाली में तकनीकी हस्तक्षेप व नियामक पक्ष को मजबूत करने की जरूरत है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation